CPO's Serial No. 40/2014.

Eastern Railway

No.E.787/0/Pen/Pt-XXVI. Kolkata, dated 15.05.2014.

ALL CONCERNED

Sub:-Amendment to the Railway Services (Pension) Rules, 1993.

****

Copy of Railway Board's letter No.2011/F(E)III/1(1)/9 dated 23.09.2013 (RBE. No. 97/2013) on the above subject is sent herewith for information, guidance and necessary action. Board's earlier letter as referred to therein had been circulated vide CPO's S.L.Nos. 21/95,37/95,46/95, 81/2000, 116/2000,30(2)/2002, 147(11)/2002, 4(1)/2005 & 24/3/2005 respectively.

DA: As above.

(S.K.Chattopadhyay)
Asstt.Personnel Officer/HQ
For Chief Personnel Officer

INDEX No.1058:- Clarification regarding amendment to the Railway Services (Pension) Rules, 1993.

Copy of Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(1)/9 dated 23.09.2013 (RBE. No. 972013) addressed to General Managers / FA&CAOs / CPOs, All Indian Railways /Production Units and copy to others is circulated herewith.

Kindly acknowledge

DA: As above.

Contd....2/-

आर बी ई सं. 97/2013

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 23.09.2013

का.आ. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2013 है।
   (2) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाए ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 (2) के परंतुक का लोप किया जाएगा और इसे 1 जनवरी, 1996 से लोप किया गया समझा जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के खंड (ख) के परंतुक में, "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए "शब्द रखे जाएंगे;

4. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

5. उक्त नियमों के नियम 45 का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 46 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:,

"46 संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति - कोई रेल सेवक जो संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ निकायों या अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि या

अंतरराष्ट्रीय पुनर्गठन और विकास बैंक या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त किया जाता है और जो उस संगठन से पेंशन प्रसुविधाओं के लिए हकदार हो जाता है अपने विकल्प पर-

(क) अपनी विदेश सेवा के संबंध में पेंशन अभिदाओं का संदाय करेगा और इन नियमों के अधीन ऐसी सेवा की पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना करेगा; या-

(ख) पूर्वोक्त संगठन के नियमों के अधीन अनुज्ञेय सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं का उपभोग करेगा और ऐसी सेवा की इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना नहीं करेगा:

परंतु यह कि किसी रेल सेवक द्वारा खंड (ख) का विकल्प दिए जाने पर उसे सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं भारत में रुपए में ऐसी तारीख ओर ऐसी रीति में संदेय होगी जो सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे :-

परंतु यह और कि रेल सेवक द्वारा संदत्त पेंशन अभिदाय, यदि कोई हो, का उसे प्रतिदाय किया जाएगा"।

7. उक्त नियमों के नियम 47 में,-

(1) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"18 वर्ष की सेवा के पश्चात् या सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष पूर्व अर्हक सेवा का सत्यापन-";

(2) उपनियम (1) में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "अठारह वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 53 के उपनियम (3) में "अनुपात में" शब्दों का लोप किया जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियंम 53 क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 53 क . किसी रेल विभाग के किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में समपरिवर्तन पर आमेलन के परिणामस्वरूप पेंशन के संदाय के लिए शर्तें

(1) रेल के किसी विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन पर उस विभाग के सभी रेल सेवक सामूहिक रूप से उस पब्लिक सैक्टर उपक्रम के उस समय तक जब तक कि वह उस उपक्रम में आमेलित नहीं कर दिए जाते हैं, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के अन्यत्र सेवा के निबंधनों पर स्थानांतरित हो जाएंगे और ऐसे स्थानांतरित रेल सेवक पब्लिक सैक्टर उपक्रम में ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, आमेलित हो जाएंगे ।

(2) केंद्रीय सरकार स्थानांतरित रेल सेवकों को रेल में प्रतिवर्तन का विकल्प या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में स्थायी आमेलन का विकल्प अनुज्ञात करेगी।

(3) प्रत्येक स्थानांतरित रेल सेवक द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(4) रेल सेवकों का पब्लिक सैक्टर उपक्रम में स्थायी आमेलन उस तारीख से ही प्रभावी होगा जिसको सरकार उनके विकल्पों को स्वीकार करे ओर ऐसी स्वीकृति की तारीख को ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और वे रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(5) पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में रेल सेवकों के आमेलन पर जिन पर वे सरकार में पद ग्रहण कर रहे थे, वह पद समाप्त हो जाएंगे।

(6) वे कर्मचारी जो रेल सेवा में प्रतिवर्तित होने का विकल्प देते हैं उनकी सरकारी अधिशिष्ट कक्ष के माध्यम से पुनः तैनाती की जाएगी।

(7) कर्मचारी, जिनके अंतर्गत अर्धस्थायी और अस्थायी कर्मचारी हैं किंतु नैमित्तिक मजदूर नहीं है, जो पब्लिक सैक्टर उपक्रम में स्थायी आमेलन का विकल्प देते हैं आमेलन की तारीख को ही पब्लिक सैक्टर उपक्रम के ऐसे नियमों और विनियमों या उपविधियों द्वारा शासित होंगे।

(8) कोई स्थायी रेल सेवक जिसे पब्लिक सैक्टर उपक्रम के एक कर्मचारी के रूप में आमेलित कर लिया गया है और उसका कुटुंब पेंशनिक फायदे (जिसके अंतर्गत पेंशन का लघुकरण, उपदान, कुटुंब पेंशन या असाधारण पेंशन भी है) का रेल और पब्लिक सैक्टर उपक्रम की गई सम्मिलित सेवा के आधार पर ऐसे पेंशनिक फायदे की संगणना के लिए पब्लिक सैक्टर उपक्रम से उसी सेवा निवृत्ति के समय या उसकी मृत्यु या उसके विकल्प पर प्रवृत्त संगणना सूत्र के आधार पर रेल के अधीन की गई सेवा के फायदे प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हकदार होगा।

"स्पष्टीकरण - पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर पेंशन या कुटुंब पेंशन की रकम की संगणना उसी भांति की जाएगी और जैसे रेल के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसी दिन की जाती है।"

(9) उपनियम (8) के अधीन किसी कर्मचारी की पेंशन की संगणना उसकी परिलब्धियों के पचास प्रतिशत या औसत परिलब्धियों इनमें से जो भी उसके लिए फायदाप्रद हो के आधार पर की जाएगी।

(10) यथास्थिति, पेंशन या कुटुंब पेंशन के अतिक्ति वह कर्मचारी जो सम्मिलित सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प देता है, औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई अनुतोष के लिए भी पात्र होगा।

(11) पेंशन और कुटुंब पेंशन का फायदा अर्धस्थायी और अस्थायी स्थानांतरित रेल सेवकों को उनकी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में पुष्टि के पश्चात् उपलब्ध होगा।

(12) किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलित कोई स्थायी रेल सेवक या अस्थायी या स्थायीवत सरकारी सेवक जिसकी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में उसके आमेलन के पश्चात् पुष्टि की गई है, सरकार और पब्लिक सैक्टर उपक्रम दोनों के पास दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के लिए पात्र होगा और ऐसा व्यक्ति अर्हक सेवा के आधार पर पेंशनिक फायदों के लिए पात्र होगा।

(13) सरकार न्यास के रूप में एक पेंशन निधि का सृजन करेगी और आमेलित कर्मचारियों के पेंशनिक फायदों को ऐसी पेंशन निधि से संदत्त किया जाएगा।

(14) रेलवे बोर्ड का सदस्य, स्टाफ, न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, संबंधित पब्लिक सैक्टर उपक्रम और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सुसंगत क्षेत्र के सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशेषज्ञ होंगे।

(15) पेंशन निधि द्वारा मंजूर और संवितरित किए जाने वाले पेंशनिक फायदों की प्रक्रिया और रीति का अवधारण न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा किया जाएगा।

(16) सरकार अपने पेंशनिक दायित्व का पालन पेंशनिक निधि, पेंशन या सेवा-उपदान और रेल सेवक की पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए सेवा निवृत्ति उपदान में एक मुश्त संदाय करके करेगी।

(17) पब्लिक सैक्टर उंपक्रम द्वारा पेंशनिक फायदों के संदाय के कारण वित्तीय दायित्व को बांटने की रीति का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा।

(18) पेंशन की एक मुश्त रकम का अवधारण रेल सेवा (पेंशन का लघुकरण) नियम, 1981 के परिशिष्ट में मूल्यों की सारणी के अनुसार किया जाएगा।

(19) पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा पेंशन निधि में उस उपक्रम के अधीन संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए उन दरों पर जो न्यासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, पेंशनिक अभिदाय किया जाएगा ताकि पेंशन निधि स्वपोषित हो।

(20) यदि किसी वित्तीय या प्रचालन कारण से न्यास, पेंशन निधि से अपने दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन करने में असमर्थ हो और पब्लिक सैक्टर उपक्रम भी कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं हो तो सरकार ऐसे व्यय को चुकाने के लिए दायी होगी और ऐसे व्यय को या तो निधि या पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नामे डाल दिया जाएगा।

(21) किसी रेलवे विभाग के किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन की तारीख को पेंशन भोगियों के फायदे के लिए पेंशनिक संदाय सरकार का उत्तरदायित्व बने रहेंगे और इस कारण उसके दायित्व को बांटने के तंत्र का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा।

(22) किसी रेलवे विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन पर-

(क) आमेलित कर्मचारियों के पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलन की तारीख को भविष्य निधि में जमा रकम ऐसे उपक्रम की सहमति से कर्मचारियों के ऐसे उपक्रम में नए भविष्य निधि खाते में अंतरित हो जाएगी।

(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश ऐसे उपक्रम को अंतरित हो जाएंगे।

(ग) पब्लिक सैक्टर उपक्रम के किसी कर्मचारी का उसके ऐसे उपक्रम में आमेलन के पश्चात्वर्ती अवचार के लिए सेवा से निलंबन या हटाना रेल के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति फायदों के समपहरण के समान नहीं होगा और उसको सेवा से हटाने या निलंबन या छटनी के उपक्रम के विनिश्चय उस उपक्रम से प्रशासनिक रूप से संबद्ध रेल मंत्रालय के पुनरीक्षण की शर्त के अधीन होंगे।

(23) सरकार द्वारा किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में इक्यावन प्रतिशत या अधिक की अपनी साम्या का अपनियोजन करने की दशा में वह ऐसे पब्लिक सैक्टर उपक्रम के आमेलित कर्मचारी के हित के संरक्षण के लिए यथेष्ट सुरक्षोपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

(24) उपनियम (23) के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षोपाय में उपक्रम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सतत् सेवा या रेल कर्मचारियों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों को लागू शर्तों पर कर्मचारियों के विकल्प पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदे और अर्हक सेवा का शिथिलीकरण के साथ अर्जित पेंशनिक फायदों का आश्वासित संदाय है, जैसा सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए।

10. उक्त नियमों नियम 53क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 53 ख किसी रेले विभाग के केंद्रीय स्वायत निकाय में संपरिवर्तन के फलस्वरूप आमेलन पर पेंशन के संदाय के लिए शर्ते-

(1) रेल के किसी विभाग के किसी स्वायत निकाय में संपरिवर्तन पर विभाग के सभी रेल सेवक एक साथ स्वायत निकाय को उस समय तक जब तक कि वह उस स्वायत निकाय में आमेलित नहीं कर दिए जाते हैं, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के अन्यत्र सेवा के निबंधनों पर स्थानांतरित हो जाएंगे और ऐसे स्थानांतरित रेल सेवक स्वायत निकाय में ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, आमेलित हो जाएंगे।

(2) सरकार, स्थानांतरित रेल सेवकों को सरकार में प्रतिवर्तन का विकल्प या स्वायत निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प अनुज्ञात करेगी।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग प्रत्येक स्थानांतरित रेल सेवक द्वारा ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(4) रेल सेवकों का स्वायत निकाय में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको सरकार उनके विकल्पों को स्वीकार करे और ऐसी स्वीकृति की तारीख से ही ऐसे कर्मचारी रेल सेवक नहीं रहेंगे ओर वे रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(5) स्वायत निकाय में रेल सेवको के आमेलन पर, जिन सरकारी पदों पर वे आमेलन पूर्व थे, वे पद समाप्त हो जाएंगे।

(6) वे कर्मचारी जो रेल सेवा में प्रतिवर्तित होने का विकल्प देते हैं, की सरकारी अधिशेष कक्ष के माध्यम से पुन: तैनाती की जाएगी।

(7) कर्मचारी जिनके अंतर्गत अर्धस्थायी और अस्थायी कर्मचारी हैं किंतु नैमित्तिक मजदूर नहीं है, जो स्वायत निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प देते हैं, आमेलन की तारीख से ही स्वायत्त निकाय के ऐसे नियमों और विनियमों या उपविधियों द्वारा शासित होंगे।

(8) कोई स्थायी रेल सेवक जिसे स्वायत निकाय के एक कर्मचारी के रूप में आमेलित कर लिया गया है और उस कुटुंब पेंशनिक फायदे (जिसके अंतर्गत पेंशन का लघुकरण, उपदान, कुटुंब पेंशन या असाधारण पेंशन भी है) का रेल और स्वायत निकाय में की गई सम्मिलित सेवा के आधार पर ऐसे पेंशनिक फायदे की संगणना के लिए स्वायत निकाय से उसकी सेवा निवृत्ति के समय या उसकी मृत्यु या उसके विकल्प पर प्रवृत्त संगणना सूत्र के

आधार पर रेल के अधीन की गई सेवा के फायदे प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हकदार होगा।

" स्पष्टीकरण - स्वायत निकाय में आमेलित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर पेंशन या कुटुंब पेंशन की रकम की संगणना उसी भांति की जाएगी जैसे रेल सेवक की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसी दिन की जाती है।"

(9) उपनियम (8) के अधीन किसी कर्मचारी की पेंशन की संगणना उसकी परिलब्धियों के पचास प्रतिशत या औसत परिलब्धियां इनमें से जो भी उसके लिए फायदाप्रद हो के आधार पर की जाएगी।

(10) यथास्थिति, पेंशन या कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त वे आमेलित कर्मचारी जो सम्मिलित सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प देते हैं, केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई अनुतोष के लिए भी पात्र होंगे।

(11) पेंशन और कुटुंब पेंशन का फायदा अर्धस्थायी और अस्थायी स्थानातंरित रेल सेवको को उनकी स्वायत निकाय में पुष्टि के पश्चात् उपलब्ध होगा।

(12) सरकार न्यास के रूप में एक पेंशन निधि का सृजन करेगी और आमेलित कर्मचारी के पेंशनिक फायदों को ऐसी पेंशन निधि से संदत्त किया जाएगा।

(13) रेलवे बोर्ड का सदस्य स्टाफ न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, संबंधित स्वायत निकाय और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सुसंगत क्षेत्र के सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशेषज्ञ होंगे।

(14) पेंशन निधि द्वारा मंजूर और संवितरित किए जाने वाले पेंशनिक फायदों की प्रक्रिया और रीति का अवधारण न्यासी बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किया जाएगा।

(15) सरकार अपने पेशनिक दायित्व का निर्वहन पेंशनिक निधि, पेंशन या सेवा उपदान और रेल सेवक की स्वायत निकाय में आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए सेवा निवृत्ति उपदान में एक मुश्त संदाय करके करेगी।

(16) स्वायत निकाय द्वारा पेंशनिक फायदों के संदाय के कारण वित्तीय दायित्व को बांटने की रीति का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा।

(17) पेंशन की एक मुश्त रकम का अवधारण रेल सेवा (पेंशन का लघुकरण) नियम, 1993 के परिशिष्ट में मूल्यों की सारणी के अनुसार किया जाएगा।

(18) स्वायत निकाय द्वारा पेंशन निधि में उस निकाय के अधीन संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए, उन दरों पर जो न्यासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, अभिदाय किया जाएगा ताकि पेंशन निधि स्वपोषित हो।

(19) यदि किसी वित्तीय या प्रचालन कारण से न्यास पेंशन निधि से अपने दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन करने में असमर्थ है और स्वायत निकाय भी कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो सरकार ऐसे व्यय को चुकाने के लिए दायी होगी और ऐसे व्यय को यथास्थिति निधि या स्वायत निकाय के नामे डाल दिया जाएगा।

(20) किसी रेलवे विभाग के किसी स्वायत निकाय में संपरिवर्तन की तारीख को पेंशन भोगियों के फायदे के लिए पेंशनिक संदाय सरकार का उत्तरदायित्व बने रहेंगे और इस निमित्त उसके दायित्व को बांटने के तंत्र का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा।

(21) किसी रेलवे विभाग के स्वायत निकाय में संपरिवर्तन पर -

(क) आमेलित कर्मचारियों के स्वायत निकाय में आमेलन की तारीख को भविष्य निधि में जमा रकम ऐसे निकाय की सहमति से कर्मचारियों के ऐसे निकाय में नए भविष्य निधि खाते में अंतरित हो जाएगी।

(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश ऐसे निकाय को अंतरित हो जाएंगे।

(ग) स्वायत निकाय के किसी कर्मचारी का उसके ऐसे निकाय में आमेलन के पश्चात्वर्ती अवचार के लिए सेवा से निलंबन या हटाना रेल के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति फायदों के समपहरण समान नहीं होगा और उसको सेवा से हटाने या निलंबन या छंटनी के निकाय के विनिश्चय उस निकाय से प्रशासनिक रूप से रेल मंत्रालय के पुनरीक्षण के अधीन होंगे।

(22) सरकार द्वारा किसी स्वायत निकाय में 51 प्रतिशत या अधिक की अपनी साम्या का अपनियोजन करने की दशा में वह ऐसे स्वायत्त निकाय के आमेलित कर्मचारी के हित के संरक्षण के लिए यथेष्ट सुरक्षोपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

(23) उपनियम (22) के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षोपायों में निकाय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सतत् सेवा या रेल कर्मचारियों या स्वायत निकाय के कर्मचारियों को लागू शर्तों पर कर्मचारियों के विकल्प पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदे और अर्हक सेवा का शिथिलीकण के साथ अर्जित पेंशनिक फायदों का आश्वासित संदाय है जैसा सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए।

11. मूल नियमों के नियम 56 के खंड (ii) के उपखंड (क) में "सात सौ पचास रुपए" के स्थान पर "इक्कीस हजार रुपए " शब्द रखे जाएंगे;

12. मूल नियमों के 64 के उपनियम (3) में "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए " शब्द रखे जाएंगे;

13. मूल नियमों के 65 के उपनियम (2) में "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए " शब्द रखे जाएंगे;

14. उक्त नियमों के नियम 67 में, - उपनियम (5) का लोप किया जाएगा।

15. उक्त नियमों के नियम 68 का लोप किया जाएगा।

16. मूल नियमों के नियम 69 में -

(1) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) सेवानिवृत्त की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता को उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में भी माना जाएगा।"

(2) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक की दशा में, पेंशन की रकम, न्यूनतम तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास और अधिकतम पैंतालीस हजार रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए परिलब्धियों का पचास प्रतिशत या औसत परिलब्धियों का पचास प्रतिशत जो उसको अधिक फायदाप्रद हो, पर संगणित की जाएगी।

(2क) उपनियम (2) के अनुसार अनुज्ञेय पेंशन के अतिरिक्त, अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के पश्चात् अतिरिक्त पेंशन निम्नलिखित रीति में सेवानिवृत्त रेल सेवकों को संदेय होगी :-

क्र.सं.	पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त पेंशन
(1)	(2)	(3)
1.	80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 20%
2.	85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 30%
3.	90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 40%
4.	95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 50%
5.	100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100%। ";

(3) उपनियम (4) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "के खंड (क) और खंड (ख)" शब्दों का लोप किया जाएगा;

17 मूल नियमों के नियम 70 में,-

(क) उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता को इस नियम के प्रयोजनों के लिए परिलब्धियों के रूप में भी माना जाएगा।";

18 मूल नियमों के नियम 71 के उपनियम (1) के खंड (ख) में,-

(क) उपखंड (i) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (I), (II), (III) और (iv)" के स्थान पर "खंड (i), खंड (ii), खंड (iii), खंड (iv) और खंड (v) "'शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (ii) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड " (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) " के स्थान पर "खंड (vi), खंड (vii), खंड (viii), खंड (ix), खंड(x) और खंड (xi)" शब्द कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

19 मूल नियमों के नियम 75 में, -

(1) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (18) के उपबंधों के अधीन और उपनियम (4)में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब किसी रेल सेवक की मृत्यु- :-

(क) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात् हो जाती है; या

(ख) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पूर्व हो जाती है परंतु यह तब जब कि संबद्ध मृतक रेल सेवक की सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षा की गई हो और प्राधिकारी द्वारा उसे रेल सेवा हेतु उपयुक्त घोषित किया गया हो; या

(ग) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् हो जाती है और वह अपनी मृत्यु की तारीख को इन नियमों में निर्दिष्ट पेंशन, अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा है ।

तो मृतक का कुटुंब, रेल सेवकों के लिए कुटुंब पेंशन स्कीम, 1964 के अधीन कुटुंब पेंशन (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् कुटुंब पेंशन कहा गया है) का हकदार होगा जिसकी रकम न्यूनतम तीन हजार पांच सौ रुपए और अधिकतम सत्ताइस हजार रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 30% की समरूप दर पर अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण-'एक वर्ष की लगातार सेवा' पद का, जहां कही भी वह इस नियम में आता है, अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत खंड (ख) में यथाउपबंधित "एक वर्ष से अन्यून लगातार सेवा भी है।";

(2) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3क) उपनियम (2), उपनियम (3), और उपनियम (4) के अनुसार अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त, अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयू पूरी करने के पश्चात् अतिरिक्त कुटुंब पेंशन निम्नलिखित रीति में संदेय होगी :-"

क्र.सं.	पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त पेंशन
(1)	(2)	(3)
1.	80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 20%

2.	85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 30%
3.	90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 40%
4.	95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष होने तक	मूल पेंशन का 50%
5.	100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100%।"

(3) उपनियम (4) में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) (क) जहां किसी ऐस रेल सेवक की, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) द्वारा शासित नहीं होता है, सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात् सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है वहां कुटुंब पेंशन की दर अंत में लिए गए वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर होगी और इस प्रकार अनुज्ञेय रकम रेल सेवक की मृत्यु की आगामी तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगी।

(ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात् रेल सेवक की मृत्यु होने की दशा में उपखंड (क) के अधीन यथा अवधारित कुटुंब पेंशन सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्त मृत रेल सेवक, यदि वह जीवित रहता तो, जिस तारीख को 67 वर्ष की आयु का हो जाता, उस तारीख तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, संदेय होगी।

परंतु इस उपखंड (ख) के अधीन अवधारित कुटुंब पेंशन की रकम किसी भी दशा में रेल सेवा से सेवानिवृत्ति होने पर मंजूर की जाने वाली पेंशन से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह और कि जहां सेवानिवृत्ति होने पर प्रधिकृत की जाने वाली पेंशन की रकम उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन की रकम से कम हो, वहां इस खंड के अधीन अवधारित पेंशन की रकम उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की रकम तक सीमित होगी।

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, सेवानिवृत्ति होने पर प्रधिकृत की जाने वाली पेंशन के अंतर्गत पेंशन का वह भाग भी है जिसे सेवानिवृत्त रेल सेवक मृत्यु से पहले संराशीकृत कर सकता है।";

(4) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (5) जहां रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कोई पंचाट अनुज्ञेय है वहां इस नियम के अधीन पंचाट के बने रहने के दौरान कोई कुटुंब पेंशन मंजूर नहीं की जाएगी।";

(5) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(6) वह अवधि जिस के लिए कुटुंब पेंशन संदेय है, वह निम्नानुसार होगी :-

(i) पहले परंतुक के अध्यधीन, विधवा अथवा विधुर की दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक इनमें से जो भी पहले हो ;

(ii) दूसरे परंतुक के अध्यधीन, अविवाहित पुत्र की दशा में जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले या जब तक वह विवाहित न हो जाए या जब तक वह अपनी जीविका उपार्जन आरंभ न कर दें, इनमें से जो पहले हो ;

(iii) दूसरे और तीसरे परंतुक के अध्यधीन अविवाहित या विधवा या परित्यक्त पुत्री की दशा में जब तक उसका विवाह अथवा पुनर्विवाह न हो जाए या जब तक वह अपनी जीविका उपार्जन आरंभ न कर कर दें, इनमें से जो भी पहले हो ;

(iv) उपनियम (10 क) के अधीन माता पिता की दशा में जो रेल सेवक की मृत्यु के ठीक पहले पूर्णतः रेल सेवक पर आश्रित थे ; जीवनभर के लिए

(v) उपनियम (10 ख) और चौथे परंतुक के अधीन, निःशक्त सहोदर (अर्थात् भाई और बहन) की दशा में, जो रेल सेवक की मृत्यु के ठीक पूर्व रेल सेवक पर आश्रित थे ; जीवनभर के लिए :

परंतु कुटुंब पेंशन, पुनर्विवाह पर निःसंतान विधवा को संदेय होना जारी रहेगी यदि सभी अन्य स्रोतों से उसकी आय, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है:

परंतु यह और कि यदि रेल सेवक का पुत्र या पुत्री जो मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, जिसमें मानसिक मंदन या शारीरिक अपंगता या निःशक्तता सम्मिलित है, जिससे उसको पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविका उर्पाजन करने में असमर्थता है, ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संज्ञेय होगी, अर्थात् :-

(क) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री, रेल सेवक के दो या दो में से अधिक बालकों में से एक है तो कुटुंब पेंशन प्रारंभतः इन नियम के उपनियम (8) के खंड (iii) में दिए गए आदेश में

अवयस्क बालकों (उपनियम के खंड (ii) या खंड (iii) में उल्लिखित) के रूप में तब तक संदेय होगी जब तक अंतिम बालक पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और तत्पश्चात् कुटुंब पेंशन उस पुत्र या पुत्री के पक्ष में जो मानसिक विकार या मस्तिष्क की निःशक्तता, जिसमें मानसिक मंदन या जो शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्तता है, सम्मिलित है, से ग्रस्त है, संदेय होगी और यह उसे आजीवन संदेय होगी ;

(ख) यदि एक या एक से अधिक ऐसे बालक मस्तिष्क के विकार या निःशक्तता, जिसमें मानसिक मंदता भी सम्मिलित है, से ग्रस्त हैं या जो शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं तो कुटुंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में संदत्त की जाएगी और उनमें से कनिष्ठ व्यक्ति कुटुंब पेंशन केवल तभी प्राप्त करेगा जब तक उससे ठीक ऊपर वरिष्ठ व्यक्ति पात्र नहीं रह जाता है :

परंतु जहां कुटुंब पेंशन ऐसे जुड़वा बालकों को संदेय है वहां इसे इस नियम के उपनियम (7) के खंड (iv) में दी गई रीति में संदत्त किया जाएगा ;

(ग) ऐसे पुत्र या पुत्री को कुटुंब पेंशन संरक्षक के माध्यम से संदत्त की जाएगी मानो वह अवयस्क होती सिवाय शारीरिक रूप से अपंग पुत्र या पुत्री के, जिसने वयस्कता की आयु को प्राप्त किया हो;

(घ) किसी ऐसे पुत्र या पुत्री के आजीवन कुटुंब पेंशन के अनुज्ञात करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि विकलांगता ऐसी प्रकृति की है जो उसे जीविका का उपार्जन करने से रोकती है और उसी को चिकित्सा निदेशक या एक प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक या एक क्षेत्रीय रेल अथवा मंडल अस्पताल के प्रभारी या उसके नामनिर्देशिती के रूप में अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य, जिसमें से कम से कम एक सदस्य मानसिक या शारीरिक निःशक्तता, जिसमें मानसिक मंदता भी शामिल हैं, के विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, के रूप में उससे मिलकर बनने वाले चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाणपत्र द्वारा साक्षयित होगा जिसमें यथासंभव बालक की सटीक मानसिक या शारीरिक दशा उपवर्जित की गई है ;

(ड़) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा व्यक्ति या ऐसा पुत्र या पुत्री जो संरक्षक के माध्यम से कुटुंब पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, एक चिकित्सा निदेशक या प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक या एक क्षेत्रीय रेल अथवा मंडल अस्पताल के प्रभारी या उसके नामनिर्देशिती के रूप में अध्यक्ष और उसके दो अन्य सदस्य जिसमें कम से कम एक सदस्य मानसिक या शारीरिक निःशक्तता, जिसमें मानसिक मंदता भी हैं, के विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, से मिलकर बनने वाले चिकित्सा बोर्ड से इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, एक बार यदि निःशक्तता स्थायी है और प्रत्येक पांच वर्ष में एक

बार, यदि नि:शक्तता अस्थायी है, कि वह मस्तिष्क के विकार या नि:शक्तता या शारीरिक अपंगता या नि:शक्तता से लगातार ग्रस्त रहता है :

(च) मानसिक रूप से मंदित पुत्र या पुत्री की दशा में कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, सरकारी सेवक या पेंशनभोगी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदेय होगी और यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन उसके जीवनकाल के दौरान रेल सेवक या पेंशनभोगी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को, यथास्थिति, ऐसे रेल सेवक या कुटुंब पेंशन भोगी के पति या पत्नी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं किया जाता है और स्थानीय स्तर समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999 का 44) की धारा 14 के अधीन जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र भी उक्त अधिनियम में यथाउपदर्शित आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के संबंध में कुटुंब पेंशन मंजूर करने के लिए संरक्षक का नामनिर्देशन या उसकी नियुक्ति के लिए भी स्वीकार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक किसी अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की मंजूरी या निरंतरता या जब तक वह विवाहित या पुनर्विवाहित नहीं हो जाती, या जब तक वह जीविका अर्जन करना प्रारंभ नहीं करती, जो भी पूर्वतर हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :-

(क) इन नियम के उपनियम (8) के खंड (iii) में दिए गए आदेश में अवयस्क बालकों (इस उपनियम के खंड (ii) या उपखंड (iii) में उल्लिखित) को कुटुंब पेंशन आरंभिक रूप से संदेय होगी जब तक अंतिम अवयस्क बालक पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है ; और

(ख) इस उपनियम के दूसरे परंतुक के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई नि:शक्त बालक पात्र नहीं है :

परंतु ऐसा नि:शक्त सहोदर, इस नियम में यथा अधिकथित उसी रीति में और आगामी उसी नि:शक्तता के मानदंड में आजीवन कुटुंब पेंशन का हकदार होगा जो रेल कर्मचारी या पेंशन भोगी के पुत्र या पुत्री की दशा में, जो मस्तिष्क के विकार या नि:शक्तता (मानसिक मंदता सहित) से ग्रस्त है, या जो शारीरिक रूप से विकलांग या नि:शक्त है जिससे कि वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् भी जीविका के उपार्जन करने में असमर्थ है, के लिए लागू हैं।

स्पष्टीकरण 1- कोई अविवाहित पुत्र या अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री इस उपनियम के अधीन उस तारीख को, जिसको वह विवाह या पुनर्विवाह कर लेता है/लेती है कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा/जाएगी।

स्पष्टीकरण 2- ऐसे किसी पुत्र या पुत्री या माता-पिता या सहोदर को देय कुटुंब पेंशन रूक जाएगी यदि वह या वे अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ कर देते हैं।

स्पष्टीकरण 3- यह पुत्र या पुत्री या सहोदर या संरक्षक का कर्त्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार, यथास्थिति, खजाना या बैंक को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि (i) उसने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है (ii) वह अभी तक अविवाहित है या वह पुनर्विवाहित नहीं है और उसी प्रकार का प्रमाण पत्र नि:संतान विधवा द्वारा उसके पुनर्विवाह के पश्चात् या माता-पिता द्वारा वर्ष में एक बार, यथास्थिति, खजाने या बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने या उन्होंने अपनी जीविका का उपार्जन आरंभ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण 4- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए कुटुंब का कोई सदस्य अपनी जीविका का उपार्जन करता समझा जाएगा यदि उसकी अन्य स्रोत से आय, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकृत महंगाई राहत से अधिक है।

स्पष्टीकरण 5- माता-पिता को सरकारी सेवक पर आश्रित समझा जाएगा यदि उनकी सम्मिलित आय इस नियम के उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत से कम है।

स्पष्टीकरण 6- नि:शक्त सहोदर रेल सेवक पर आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी आय इस नियम के उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और दस पर महंगाई राहत से कम है।

स्पष्टीकरण 7- नि:संतान विधवा को देय कुटुंब पेंशन रोक दी जाएगी, यदि पुनर्विवाह के पश्चात् उसकी अन्य स्रोतों से आय इस नियम के उपनियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या अधिक हो जाती है।

(6) उपनियम (7) में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) जहां कुटुंब पेंशन जुड़वा बच्चों को संदेय है, यह ऐसे बच्चों को समतुल्य भागों में संदत्त की जाएगी:

परंतु जब ऐसा एक बालक पात्र नहीं रह जाए जो उसका भाग दूसरे बालक को चला जाएगा ओर जब वे दोनों कुटुंब पेंशन के पात्र होना बंद हो जाए तो कुटुंब पेंशन अगले पात्र, यथास्थिति, एकल या जुड़वा बच्चों को संदेय होगी।

(7) उपनियम (8) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् -

" (iii) बच्चों को कुटुंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में संदेय होगी और उनमें से छोटा कुटुंब पेंशन का पात्र नहीं होगा, जब तक कि उससे बड़ा बच्चा कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए अपात्र नहीं बन जाए :

परंतु जहां कुटुंब पेंशन जुड़वा बच्चों को संदेय है, वहां उपनियम (7) के खंड (iv) में वर्णित रीति से इसका संदाय किया जाएगा।

(8) उपनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

"(10 क) (i) माता-पिता को कुटुंब पेंशन संदेय होगी यदि माता-पिता, रेल सेवक की अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों और मृत सरकारी सेवक का कोई विधवा या पात्र बालक जीवित न हो।

(ii) कुटुंब पेंशन, जब कभी माता-पिता को अनुज्ञेय हो, मृत रेल सेवक की मां को संदेय होगी जिसके न हो सकने पर मृत रेल सेवक के पिता को संदेय होगी।

(10 ख) आश्रित नि:शक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन संदेय होगी यदि सहोदर मृत रेल सेवक की उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व रेल सेवक पर आश्रित था और मृत रेल सेवक का कोई विधवा या पात्र बालक या पात्र माता-पिता जीवित नहीं है।";

(9) उपनियम 11 में,

(1) खंड (क) में, उपखंड (i) और (ii) में "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पैंतालीस हजार रुपए" शब्द रख जाएंगे;

(2) खंड (ख) में, "एक हजार दो सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "सत्ताइस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(10) उपनियम (13) में खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) उपनियम (12) के परंतुक के अधीन रहते हुए, इस नियम के अधीन, बालक या बालकों का कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं रहने के पश्चात् ऐसी कुटुंब पेंशन मृत रेल सेवक के न्यायिक रूप से पृथक् उत्तरजीवी पति या पत्नी को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह होने तक जो भी पूर्वत्तर हो संदेय हो जाएगी।";

(11) उपनियम (15) के खंड (ii) में "महिला" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(12) उपनियम 17 का लोप किया जाएगा।

(13) उपनियम 18 का लोप किया जाएगा ।

(14) उपनियम (19) के खंड (ख) में उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(iii)अविवाहित पुत्र, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक ग्रहीत पुत्र या पुत्री भी हैं ;

(iv) आश्रित माता-पिता ;

(v) रेल सेवक का आश्रित निःशक्त सहोदर (अर्थात् भाई या बहन) ।";

(15) उपनियम (20) में खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

(फाइल से. 2011/एफ (ई) III/1 (1)/9)

संजय लवाणिया

(संजय लवाणिया)
कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड

टिप्पण: मूल नियम का.आ. 930 (अ) तारीख 3 दिसंबर 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

I. का.आ. 511, तारीख 25-2-1995.
II. का.आ. 1026, तारीख 15-4-1995.
III. का.आ. 1553, तारीख 15-7-2000.
IV. का.आ. 1554, तारीख 15-7-2000.
V. का.आ. 1081, तारीख 30-3-2002.
VI. का.आ. 1488(इ), तारीख 30-12-2003.
VII. का.आ. 1214(इ), तारीख 04-11-2004.
VIII. का.आ. 3191, तारीख 18-12-2004.
IX. का.आ. 399, तारीख 05-02-2005
X. का.आ. 1001, तारीख 19-03-2005.
XI. का.आ. 1306, तारीख 08-04-2006.
XII. का.आ. 3005, तारीख 13-10-2007.
XIII. का.आ. 2944, तारीख 25-10-2008.

संजय लवाणिया

(संजय लवाणिया)
कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड

RBE No. 97 /2013

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

Notification

New Delhi, dated the 23.09.2013.

S.O. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Pension) Rules, 1993, namely:-

1. (1) These rules may be called the Railway Services (Pension) Amendment Rules, 2013.

(2) Save as otherwise expressly provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993, (hereinafter referred to as the said rules) the proviso to sub-rule (2) of rule 6 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of January, 1996.

3. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (b), in the proviso, for the words "rupees three hundred and seventy five", the words "rupees three thousand five hundred" shall be substituted;

4. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (1), in the second proviso, for the words "rupees three hundred and seventy-five", the words "rupees three thousand five hundred" shall be substituted;

5. Rule 45 of the said rules, shall be omitted;

6. For rule 46 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:–

"46. Deputation to United Nations and other organisations.- A railway servant who is deputed on foreign service to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organisation and who becomes entitled for pensionary benefits from that organisation, may at his option,- .

(a) pay the pension contributions in respect of his foreign service and count such service as qualifying for pension under these rules; or

(b) avail the retirement benefits admissible under the rules of the aforesaid organisation and not count such service as qualifying for pension under these rules:

Provided that where a railway servant opts for clause (b), retirement benefits shall be payable to him in India in rupees from such date and in such manner as the Government may, by order, specify:

Provided further that pension contributions, if any, paid by the railway servant, shall be refunded to him".

7. In rule 47 of the said rules, -

(1) for the marginal heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Verification of qualifying service after eighteen years' service or five years before retirement.-" ;

(2) in sub-rule(1), for the words "twenty five years", the words "eighteen years" shall be substituted;

8. In rule 53 of the said rules, in sub-rule (3), the words "pro rata" shall be omitted;

9. For rule 53A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely;–

"53A. Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Railway Department into a public sector undertaking.—

(1) On conversion of a Department of the Railway into a public sector undertaking, all railway servants of that Department shall be transferred en-masse to that public sector undertaking, on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said undertaking, and such transferred railway servants shall be absorbed in the public sector undertaking with effect from such date as may be notified by the Government.

(2) The Government shall allow the transferred railway servants an option to revert back to the railway or to seek permanent absorption in the public sector undertaking.

(3) The option referred to in sub-rule (2) shall be exercised by every transferred railway servant in such manner and within such period as may be specified by the Government.

(4) The permanent absorption of the railway servants as employees of the public sector undertaking shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the

date of such acceptance, such employees shall cease to be Government servants and they shall be deemed to have retired from railway service.

(5) Upon absorption of railway servants in the public sector undertaking, the posts which they were holding in the Government before such absorption shall stand abolished.

(6) The employees who opt to revert to railway service shall be redeployed through the surplus cell of the Government.

(7) The employees including quasi-permanent and temporary employees but excluding casual labourers, who opt for permanent absorption in the public sector undertaking shall, on and from the date of absorption, be governed by the rules and regulations or bye-laws of the public sector undertaking.

(8) A permanent railway servant who has been absorbed as an employee of a public sector undertaking and his family shall be eligible for pensionary benefits (including commutation of pension,. gratuity, family pension or extra-ordinary pension), on the basis of combined service rendered by the employee in the Railways and in the public sector undertaking in accordance with the formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force at the time of his retirement from the public sector undertaking or his death or at his option, to receive benefits for the service rendered under the Railways in accordance with the orders issued by the Government.

Explanation:- The amount of pension or family pension in respect of the absorbed employee on retirement from the public sector undertaking or on death shall be calculated in the same way as calculated in the case of a railway servant retiring or dying on the same day.

(9) The pension of an employee under sub-rule (8) shall be calculated on fifty per cent. of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him.

(10) In addition to pension or family pension, as the case may be, the employee who opts for pension on the basis of combined service shall also be eligible to dearness relief as per industrial dearness allowance pattern.

(11) The benefits of pension and family pension shall be available to quasi-permanent and temporary transferred railway servants after they have been confirmed in the public sector undertaking.

(12) A permanent railway servant absorbed in a public sector undertaking or a temporary or quasi-permanent railway servant who has been confirmed in a public sector undertaking subsequent to his

absorption therein, shall be eligible to seek voluntary retirement after completing ten years of qualifying service with the Government and the public sector undertaking taken together, and such person shall be eligible for pensionary benefits on the basis of qualifying service.

(13) The Government shall create a pension fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such pension fund.

(14) The Member Staff, Railway Board shall be the Chairperson of the Board of Trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance, Personnel, Public Grievances and Pensions, Labour, concerned public sector undertaking and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Government.

(15) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the pension fund shall be determined by the Government on the recommendations of the board of trustees.

(16) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the pension fund the pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the railway servant in the public sector undertaking.

(17) The manner of sharing the financial liablity on account of payment of pensionary benefits by the public sector undertaking shall be determined by the Government.

(18) Lump sum amount of the pension shall be determined in accordance with the Table of the values in Appendix to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(19) The public sector undertaking shall make pensionary contribution to the pension fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that undertaking at the rates as may be determined by the board of trustees so that the pension fund shall be self-supporting.

(20) If, for any financial or operational reason, the trust is unable to discharge its liabilities fully from the Pension Fund and the public sector undertaking is also not in a position to meet the shortfall, the Government shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the fund or to the public sector undertaking.

(21) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a railway Department on the date of conversion of it into a public sector undertaking shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.

(22) Upon conversion of a Railway Department into a public sector undertaking,-

(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the public sector undertaking shall with the consent of such undertaking, be transferred to the new provident fund account of the employees in such undertaking;

(b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such undertaking;

(c) the dismissal or removal from service of the public sector undertaking of any employee after his absorption in such undertaking for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Railways and in the event of his dismissal or removal or retrenchment, the decisions of the undertaking shall be subject to review by the Ministry of Railways with the undertaking.

(23) In case the Government disinvests its equity in any public sector undertaking to the extent of fifty-one per cent or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such public sector undertaking.

(24) The safeguards specified under sub-rule (23) shall include option for voluntary retirement or continued service in the undertaking or voluntary retirement benefits on terms applicable to railway servants or employees of the public sector undertaking as per option of the employees and assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.".

10. After rule 53A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"53B. Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Railway Department into a Central autonomous body, -

(1) On conversion of a Department of the Railway into an autonomous body, all railway servants of that Department shall be transferred en-masse to that autonomous body on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said body and such transferred

railway servants shall be absorbed in the autonomous body with effect from such date as may be notified by the Government.

(2) The Government shall allow the transferred railway servants an option to revert back to the Government or to seek permanent absorption in the autonomous body.

(3) The option referred to in sub-rule (2) shall be exercised by every transferred railway servant in such manner and within such period as may be specified by the Government.

(4) The permanent absorption of the railway servants of the autonomous body shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be railway servants and they shall be deemed to have retired from railway service.

(5) Upon absorption of railway servants in the autonomous body, the posts which they were holding in the Government before such absorption shall stand abolished.

(6) The employees who opt to revert to railway service shall be redeployed through the surplus cell of the Government.

(7) The employees including quasi-permanent and temporary employees but excluding casual labourers, who opt for permanent absorption in the autonomous body, shall on and from the date of absorption, be governed by the rules and regulations or bye-laws of the autonomous body.

(8) A permanent railway servant who has been absorbed as an employee of an autonomous body and his family shall be eligible for pensionary benefits (including commutation of pension, gratuity, family pension or extra-ordinary pension), on the basis of combined service rendered by him in the Railways and autonomous body in accordance with the formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force at the time of his retirement from the autonomous body or death or at his option, to receive benefits for the service rendered under the Railways in accordance with the orders issued by the Government.

Explanation:- The amount of pension or family pension in respect of the absorbed employee on retirement from autonomous body or death shall be calculated in the same way as would be the case with a railway servant retiring or dying on the same day.

(9) The pension of an employee under sub-rule (8) shall be calculated at fifty per cent. of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him.

(10) In addition to pension or family pension, as the case may be, the absorbed employees who opt for pension on the basis of combined service shall also be eligible to dearness relief as per central dearness allowance pattern.

(11) The benefits of pension and family pension shall be available to quasi permanent and temporary transferred railway servants after they have been confirmed in the autonomous body.

(12) The Government shall create a pension fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such pension fund.

(13) The Member Staff, Railway Board shall be the Chairperson of the board of trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance, Personnel, Public Grievances and Pensions, Labour, concerned autonomous body and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Government.

(14) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the pension fund shall be determined by the Government on the recommendations of the board of trustees.

(15) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the pension fund the pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the railway servant in the autonomous body.

(16) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the autonomous body shall be determined by the Government.

(17) Lump sum amount of the pension shall be determined in accordance with the Table of the values in Appendix to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(18) The autonomous body shall make pensionary contribution to the pension fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that body at the rates as may be determined by the Board of Trustees so that the pension fund shall be self-supporting.

(19) If, for any financial operational reason, the trust is unable to discharge its liabilities fully from the pension fund and the autonomous body is also not in a position to meet the shortfall, the Government shall

be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the fund or to the autonomous body, as the case may be.

(20) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a Railway Department on the date of conversion of it into an autonomous body shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.

(21) Upon conversion of a Department of the Railway into an autonomous body.–

(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the autonomous body shall, with the consent of such body, be transferred to the new provident fund account of the employees in such body;

(b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such body;

(c) the dismissal or removal from service of the autonomous body of any employee after his absorption in such body for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Railways and in the event of his dismissal or removal or retrenchment, the decisions of the body shall be subject to review by the Ministry of Railways.

(22) In case the Government disinvests its equity in any autonomous body to the extent of fifty-one per cent. or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such autonomous body.

(23) The safeguards specified under sub-rule(22) shall include option for voluntary retirement or continued service in the body, as the case may be or voluntary retirement benefits on terms applicable to railway employees or employees of the autonomous body as per option of the employees, assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.".

11. In rule 56 of the said rules, in clause (ii), in sub clause (a), for the words "seven hundred and fifty rupees", the words "twenty-one thousand rupees" shall be substituted;

12. In rule 64 of the said rules, in sub-rule (3), for the words " three hundred seventy five rupees ", the words " three thousand five hundred rupees " shall be substituted;

13. In rule 65 of the said rules, in sub-rule (2), for the words "three hundred seventy five rupees ", the words" three thousand five hundred rupees" shall be substituted;

14. In rule 67 of the said rules, sub-rule (5) shall be omitted;

15. Rule 68 of the said rules shall be omitted;

16. In rule 69 of the said rules,-

(1) after sub - rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

"(1A) The dearness allowance admissible on the date of retirement shall also be treated as emoluments for the purpose of sub-rule (1)." ;

(2) for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely;–

"(2) In the case of a railway servant retiring in accordance with the provisions of these rules after completing the qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty per cent. of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of three thousand and five hundred rupees per mensem and a maximum of forty-five thousand rupees per mensem.

(2A) In addition to pension admissible in accordance with the provisions of sub-rule (2), after completion of eighty years of age and above, the additional pension shall be payable to a retired railway servant in the following manner, namely:-

S.No.	Age of pensioner	Additional pension
(1)	(2)	(3)
1.	From 80 years to less than 85 years	20 per cent. of basic pension
2.	From 85 years to less than 90 years	30 per cent. of basic pension
3.	From 90 years to less than 95 years	40 per cent. of basic pension
4.	From 95 years to less than 100 years	50 per cent. of basic pension
5.	100 years or more	100 per cent. of basic pension.";

(3) in sub-rule (4), the words, brackets and letters " clause (a) or clause (b) of " shall be omitted;

17. In rule 70 of the said rules, -

(1) In sub-rule (1), in the first proviso, for the words "rupees one lakh", the words "rupees ten lakh " shall be substituted;

(2) In sub-rule (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the dearness allowance admissible on the date of retirement or death, as the case may be, shall also be treated as emoluments for the purpose of this rule,";

18. In rule 71 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (b),-

(1) in sub-clause (i), for the words, brackets and figures "clauses (i), (ii), (iii) and (iv)", the words, brackets and figures "clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v)" shall be substituted;

(2) in sub-clause (ii), for the words, brackets and figures "clauses (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi)", the words, brackets and figures "clauses (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi)" shall be substituted;

19. In rule 75 of the said rules,-

(1) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

"(2) Subject to the provisions of sub-rule (18) and without prejudice to the provisions contained in sub-rule (4), where a railway servant dies,

(a) after completion of one year of continuous service; or

(b) before completion of one year of continuous service, provided the deceased railway servant concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by the appropriate medical authority and declared fit by that authority for railway service; or

(c) after retirement from service and was on the date of death in receipt of a pension, or compassionate allowance, referred to in these rules,

the family of the deceased shall be entitled to family pension (hereinafter in this rule referred to as family pension) under the Family Pension Scheme for Railway Servants, 1964, the amount of which shall be determined at a uniform rate of thirty per cent. of basic pay subject to a minimum of three thousand and five hundred rupees per mensem and a maximum of twenty-seven thousand rupees per mensem.

Explanation. - The expression "one year of continuous service" wherever it occurs in this rule, shall be construed to include less than one year of continuous service, as provided in clause (b).";

(2) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3 A) In addition to family pension admissible in accordance with sub rules (2), (3) and (4), after completion of eighty years of age and above, additional family pension shall be payable in the following manner:-

S.No.	Age of pensioner	Additional pension
(1)	(2)	(3)
1.	From 80 years to less than 85 years	20 per cent. of basic pension
2.	From 85 years to less than 90 years	30 per cent. of basic pension
3.	From 90 years to less than 95 years	40 per cent. of basic pension
4.	From 95 years to less than 100 years	50 per cent. of basic pension
5.	100 years or more	100 per cent. of basic pension.";

(3) in sub-rule (4), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) (a) Where a railway servant, who is not governed by the Employees' Compensation Act, 1923 (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent. of the pay last drawn and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the railway servant for a period of ten years.

(b) in the event of death of a railway servant after retirement, the family pension as determined under sub-clause (a) shall be payable for a period of seven years, or for a period up to the date on which the retired deceased railway servant would have attained the age of sixty-seven years had he survived, whichever is less:

Provided that in no case the amount of family pension determined under sub-clause (b) shall exceed the pension authorised on retirement from railway service.

Provided further that where the amount of pension authorised on retirement is less than the amount of family pension admissible under sub-rule (2), the amount of family pension determined under this clause shall be limited to the amount of family pension admissible under sub-rule (2).

Explanation. - For the purpose of this sub-clause, pension authorised on retirement includes the part of the pension which the retired railway servant may have commuted before death.";

(4) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

"(5) Where an award under the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 is admissible, no family pension under this rule shall be authorised during the currency of award.";

(5) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) The period for which family pension is payable shall be as follows:–

(i) subject to first proviso, in the case of a widow or widower, up to the date of death or re-marriage, whichever is earlier;

(ii) subject to second proviso, in the case of an unmarried son, until he attains the age of twenty-five years or until he gets married or until he starts earning his livelihood, whichever is the earliest;

(iii) subject to second and third provisos, in the case of an unmarried or widowed or divorced daughter, until she gets married or remarried or until she starts earning her livelihood, whichever is earlier;

(iv) subject to sub-rule (10 A), in the case of parents, who were wholly dependent on the railway servant immediately before the death of the railway servant, for life;

(v) subject to sub-rule (10 B) and the fourth proviso, in the case of disabled siblings (i.e. brother and sister) who were dependent on the railway servant immediately before the death of railway servant, for life:

Provided that family pension shall continue to be payable to a childless widow on re-marriage, if her income from all other sources is less than the amount of minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon:

Provided further that if the son or daughter of a railway servant is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely :-

(a) if such son or daughter is one among two or more children of the railway servant, the family pension shall be initially payable to the minor children (mentioned in clause (ii) or clause (iii) of this sub-rule) in the order set out in clause (iii) of sub-rule (8) of this rule until the last child attains the age of twenty-five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind, including the mentally retarded, or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her, for life;

(b) if there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind including the mentally retarded or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them shall get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible:

Provided that where the family pension is payable to such twin children it shall be paid in the manner set out in clause (iv) of sub-rule (7) of this rule;

(c) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of the physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(d) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the handicap is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a Medical Board comprising of a Medical Director or a Chief Medical Superintendent or incharge of a Zonal Hospital or Division or his nominee as Chairperson and two other members, out of which at least one shall be a specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(e) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce a certificate, from a Medical Board comprising of a Medical Director or a Chief Medical Superintendent or incharge of a Zonal Hospital or Division or his nominee as Chairperson and two other members, out of which at least one shall be a

specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation, once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every five years to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled;

(f) in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension shall be payable to a person nominated by the railway servant or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such railway servant or pensioner during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such railway servant or family pensioner, as the case may be, later on and the guardianship certificate issued under section 14 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999 (44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of person(s) suffering from autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities as specified in the said Act:

Provided that the grant or continuance of family pension to an unmarried or widowed or divorced daughter beyond the age of twenty-five years or until she gets married or re-married or until she starts earning her livelihood, whichever is the earliest, shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) the family pension shall be initially payable to the minor children (mentioned in clause (ii) or clause (iii) of this sub-rule) in the order set out in clause (iii) of sub-rule (8) of this rule until the last minor child attains the age of twenty-five years; and

(b) there is no disabled child eligible to receive family pension in accordance with the second proviso of this sub-rule:

Provided that such disabled siblings shall be eligible for family pension for life in the same manner and following the same disability criteria, as laid down in this rule in the case of son or daughter of the railway employees or pensioners suffering from any disorder or disability of mind (including mentally retarded) or physically crippled or disabled, so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years.

Explanation 1.- An unmarried son or an unmarried or widowed or divorced daughter, except a disabled son or daughter become ineligible for family pension under this sub-rule from the date he or she gets married or remarried.

Explanation 2.- The family pension payable to such a son or a daughter or parents or siblings shall be stopped if he or she or they start earning his or her or their livelihood.

Explanation 3.- It shall be the duty of son or daughter or siblings or the guardian to furnish a certificate to the Treasury or Bank, as the case may be, once in a year that, (i) he or she has not started earning his or her livelihood, and (ii) he or she has not yet married or remarried and a similar certificate shall be furnished by a childless widow after her re-marriage or by the disabled son or daughter or parents to the Treasury or

Bank, as the case may be, once in a year that she or he or they have not started earning her or his or their livelihood.

Explanation 4 .- For the purpose of this sub-rule, a member of the family shall be deemed to be earning his or her livelihood if his or her income from other sources is equal to or more than the minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon.

Explanation 5 .- Parent shall be deemed to be dependent on the railway servant if their combined income is less than the minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon.

Explanation 6.- Disabled sibling shall be deemed to be dependent on the railway servant if their income is less than the minimum family pension admissible under sub-rule (2) of this rule and dearness relief thereon.

Explanation 7 .- Family pension payable to a childless widow shall be stopped if, after re-marriage, her income from all other sources becomes equal to or exceeds the amount of minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon";

(6) in sub-rule (7), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv) where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares:

Provided that when one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and when both of them cease to be eligible the family pension shall be payable to the next eligible single or twin children as the case may be.";

(7) in sub-rule (8), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) Family pension to the children shall be payable in the order of their birth and the younger of them will not be eligible for family pension unless the elder next above to him has become ineligible for the grant of family pension:

Provided that where the family pension is payable to twin children, it shall be paid in the manner set out in clause (iv) of sub-rule (7) .";

(8) after sub-rule (10), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(10 A) (i) The family pension to the parents shall be payable if the parents were wholly dependent on the railway servant immediately before his or her death and the deceased railway servant is not survived by a widow or an eligible child.

(ii) The family pension, wherever admissible to parents, shall be payable to the mother of the deceased railway servant failing which to the father of the deceased railway servant.

(10 B) The family pension to the dependent disabled siblings shall be payable if the siblings were wholly dependent upon the railway servant immediately before his or her death and deceased railway servant is not survived by a widow or an eligible child or eligible parents.";

(9) in sub-rule 11,

(1) in clause (a), in sub-clauses (i) and (ii) for the words, " two thousand five hundred rupees", the words " forty - five thousand rupees" shall be substituted;

(2) in clause (b), for the words, " one thousand two hundred fifty rupees", the words " twenty seven thousand rupees" shall be substituted;

(10) in sub-rule (13), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:–

"(iii) Subject to the proviso of sub-rule (12), after the child or children cease to be eligible for family pension under this rule, such family pension shall become payable to the surviving judicially separated spouse of the deceased railway servant till his or her death or remarriage, whichever is earlier.";

(11) in sub-rule (15), in clause (ii), the word 'female' shall be omitted;

(12) sub-rule 17 shall be omitted;

(13) sub-rule 18 shall be omitted;

(14) in sub-rule (19), in clause (b) for sub-clause (iii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

"(iii) unmarried son who has not attained the age of twenty-five years and unmarried or widowed or divorced daughter, including such son and daughter adopted legally;

(iv) dependent parents;

(v) dependent disabled siblings(i.e. brother or sister) of a railway servants.";

(15) in sub-rule (20), clause (c) shall be omitted.

(File No. 2011/F(E)II/1(1)9)

Sanjay Lavania
(Sanjay Lavania)
Executive Director Finance(Establishment),
Railway Board.

Note:- The principal rules were published vide number S.O. 930 (E), dated the 3rd December, 1993 and subsequently amended vide the following notifications, namely:-

(i) S.O. 511, dated the 25th February,1995;

(ii) S.O.1026, dated the 15th April,1995;

(iii) S.O. 1553, dated the 15th July,2000;

(iv) S.O.1554, dated the 15th July,2000;

(v) S.O.1081, dated the 30th March,2002;

(vi) S.O. 1488 (E), dated the 30th December,2003;

(vii) S.O.1214 (E), dated the 4th November,2004;

(viii) S.O.3191, dated the 18th December,2004;

(ix) S.O.399, dated the 5th February,2005;

(x) S.O.1001, dated the 19th March,2005;

(xi) S.O.1306 dated the 8th April,2006;

(xii) S.O.3005 dated the 13th October,2007;

(xiii) S.O.2944 dated the 25th October,2008.

(File No. 2011/F(E)III/1(1)9)

Lavania

(SANJAY LAVANIA)
Executive Director Finance (Estt.),
Railway Board.

No. 2011/ F(E)III/1(1)/9 **New Delhi, Dated: 23.9.2013.**

Copy forwarded to the General Managers & FA&CAOs, All Zonal Railways & Productio Units/RDSO etc. (As per standard mailing list).

(Sukhender Kau
Joint Director Finance(Estt
Railway Boar

No. 2011/ F(E)III/1(1)/9 **New Delhi, Dated: 23.9.2013.**

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhava New Delhi (40 spares).

for Financial Commissioner/Railway

No. 2011/ F(E)III/1(1)/9 **New Delhi, Dated: 23.9.2013.**

Copy forwarded to:

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Coun 13-c, Feroze Shah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
5. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No. 402, Rail Bhawan.
6. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
9. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
10. The Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110 001. (5 spares)
11. The Secretary, Railway Board Promottee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhavan, Ne Delhi.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Ra Bhavan, New Delhi.

for Secretary/Railway Boar

No. 2011/ F(E)III/1(1)/9 **New Delhi, Dated: 23.9.2013.**

1. The G.M, N.F Railway(Const.).
2. The Director General and Ex.officio General Manager, RDSO/Lucknow.
3. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Kolkata.
4. The CAOand FA&CAO, COFMOW/New Delhi.
5. The General Manager and FA&CAO, CORE/Allahabad.
6. Director General, Railway Staff College/Vadodara.

7.The Executive Director, CAMTECH/Gwalior-474020
8.The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road,IRIMEE/Jamalpur, IRISET/ Secunderabad.
9.The Managing Director, IRCON, IRFC, MRVC, IRWO, IRC&TC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS.
10. The Chairman -cum-Managing Director, KRC Limited/New Delhi
11. Office of the Chief Project Administrator(Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom(IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi.
12. The Director(Movement) Railways/Kolkata.
13. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence.
14. The Joint Secretary, Iron & Steel,5 Koila Ghat Street/Kolkata.
15. Chief Mining Advisor, Ministry of Railway, Dhanbad, Bihar
16. The Chairman, RCC,Lok Sabha Secretariat/New Delhi.
17. The Chairman, RCT/Delhi.
18. The Chairman,RRT, Chennai.
19.The Chairman,RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad, and Trivandrum.
20. The Editor, " Bharatiya Rail".
21. The Editor " Indian Railways"
22. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board) with 5 spares.
23 The General Secretary, IRCA/New Delhi.
24 The Chief Commissioner of Railway Safety/Lucknow.
25 Chairman, RITES.
26 Chairman, CAT.
27.The Managing Director, Rail Vikas Nigam Ltd., Plot No. 25, First Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.
28. Manager/HRD,Rail Land Development Authority, Near Safdarjung Railway Station, Motibagh-1,New Delhi – 110021. Email: mgrhrd@rlda.in
29. The Chief Mechanical Engineer, Indian Railway Organisation for Alternate Fuels, 12th Floor, Core-1, Scope Minar, District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-92.
30. Office of the Chief Administrative Officer, Indian Railways (Workshop Projects), Chamber Bhawan, Judge's Court Road,Anta Ghat,Patna-800001, Bihar.
31. The Chief Administrative Officer, Rail Coach Factory/Raebareli Project, Kishanganj,Delhi-7.

Copy to:-

1. Shri V.K. Sthanunathan, National President, National Federation of Railway Pensioners,36, Venkatanarayana Road, T. Nagar, Chennai-600 017.
2. Shri K. Gopinath Menon, The Secretary General, National Federation of Railway Pensioners, Kunnathurmedu, Palghat- 678 013.
3. Shri Y.N.Sastry, President, AIRRF, Rly Block-303, Railway Colony High School, Chilkalguda, Secunderabad-500 025.
4. B. Jayajaya Rao, President, All India Retired Railway Officer's Association, 12-13-268 (505)New, Street-2, Lane 9, Tarnaka, Secunderabad-500 017.
5. The General Secretary, Railway Pensioners' Council Kiran Kutir, Larkania Tola, Katihar.
6. The General Secretary, All India Federation of Pensioners Association, T.P.M Hall,22, Kavirai Street, Saidapet West, Chennai-600 015.
7. Shri S.S.Ramachandra, Secretary General , All India Central Committee of Pensioners Association. Flat No.144, New Suryakiran Apartments, Plot No.65,Patparganj, N.Delhi-110092.
8. Shri M.S.Solanki, General Secretary, Central and AIS Pensioners Association, E-I/164, Arena Colony, Bhopal(M.P) 462 016
9. Shri Nirmal Dass Gupta, Vice President, Federation of Central Government Pensioners' Organisation, P-24C, Sagar Manna Road, Kolkata. 700 060
10. Shri B.S Dard, Secretary General, Central Government Pensioners' Association, 1874/2, Sector-64, S.A.S Nagar, Chandigarh 160 061.
11. Shri C.R. Chatwani, Central Government Pensioners' Association, "SHIVANAND", 11/13, Krishna Kunj

Society, Chhotunagar-7, Raiya Road, Rajkot 360 001.
12. Secretary General, Bharat Pensioners' Samaj, Post Box 3303, Jangpura Extension, New Delhi-110 014.
13 The Secretary General, National Federation of Railway Pensioners' Organization, 825, Supertech Residency, Sector-5, Plot No. 6A, Ghaziabad-201010.
14. M/s. Bahri Bros., Publishers, Booksellers & Distributors, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110006.
15. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association(Regd), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

Copy to:-

PSOs/Sr. PPSs/ PPSs/PSs/PAs to: MR, MSR(B), MSR(M), CRB, FC, MT, ME, MS, MM, ML, DG(RHS), DG(RPF), Secretary, All Additional Members, Adv.(S) , All Executive Directors, IG/RPSF, JS, JS(G), JS(E), DE(Res)I & II, DE(GC), DE(G), DE(N), DE (Rep), DPC-I, II, DS(D), DS(E), DS(G),), JDMPP), JDE(N), JDF(E),JDE(Rep), JDPC-VI, JDE(G), JDE(D&A), JDE(P&A), JDE(Gaz), JDE(W), JDE(GP), JDE(Res), JDE(L), JDE(LR), DDF(E)-I,II DDE(LR)I,II,III, DDE(R)II, DDE(D&A), DDE(P&A)II, III, DDE(Rep)I, US(A), US(E), W.O./Railway Board.

Cash-I, II, III, E(P&A)/II, E(G), E(NG)I&II, PC-VI, V, IV, III, E(Trg), E(MPP), E(LR)I&II, F(E)-I, II, F(E)Spl, Security(E), Security(ABE), Accounts-III, Accounts (Insp.), ERB-I, II, III, IV, V & D, G(Pass), G(Acc), E(Welfare), E(SCT) I & II, E(O)I, II, III & III(CC), E(GR)I, II, E(GP), E(GC), PR, E(D&A), Budget, O&M, Code Revision Cell(with 2 spares), C&IS (with 2 spares)A/Cs-II, PG, E(Rep)-I, II, III, Railway Board.

(Copy to DOP&PW w.r.t. to their Gazette Notification No. G.S.R. 176 dated 08.06.2011, G.S.R. 928(E) dated 21.12.2012 and G.S.R. 938(E) dated 27.12.2012.)

****